मंगलवार , 03 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 68

CITY NEWS MUMBAI

सरनाईक के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल

शिवसेना की महिला पदाधिकारी आईना लेकर पहुंचीं; दोनों पक्ष आमने-सामने, पुलिस ने किया गिरफ्तार!







भायंदर, (सिटी न्यूज़ मुंबई)

मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भाजपा ने भायंदर के नवघर और मीरा रोड में मोर्चा खोलते हुए जोरदार राजनीतिक हमला बोला। मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने उनके कथित कारनामों को जनता के सामने उजागर करने का ऐलान किया। लेकिन आंदोलन के बीच अचानक शिवसेना की महिला पदाधिकारियों की एंट्री ने पूरे घटनाक्रम को गरमा दिया। हाथों में आईना लेकर पहुंचीं करीब 20 से 25 महिला पदाधिकारियों ने भाजपा आंदोलनकारियों के सामने खड़े होकर विरोध जताया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भाजपा की ओर से उपमहापौर ध्रुव किशोर पाटिल, जिला अध्यक्ष दिलीप जैन, प्रशांत दलवी समेत अन्य नगरसेवक और पदाधिकारी मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भाषणों के जरिए तीखे आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान शिवसेना की महिला पदाधिकारी आईना लेकर पहुंच गईं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस महकमे में अफरातफरी मच गई। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस बल तैनात था। दोनों दलों के पदाधिकारी आमने-सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस तुरंत हरकत में आई। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से शिवसेना की महिला पदाधिकारियों को पुलिस वैन में बैठाकर नवघर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि कुछ अन्य महिलाओं को पैदल पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

शिवसेना के पदाधिकारियों की तस्वीरों पर चप्पलें बरसाईं

भाजपा ने अपने आंदोलन के दौरान शिवसेना के पुराने विरोध प्रदर्शन का जवाब भी अपने अंदाज में दिया। भाजपा नेताओं ने शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों की तस्वीरों पर जमकर चप्पलें और जूते बरसाए। भाजपा का कहना था कि जब शिवसेना ने भाजपा के 16 नगरसेवकों के खिलाफ इसी तरह का प्रदर्शन किया था, तो अब उसे भी उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष दिलीप जैन ने कहा कि वे मंत्री प्रताप सरनाईक का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके पोस्टर के साथ ऐसा नहीं किया गया। हालांकि शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू भाईर, विक्रम प्रताप सिंह और अन्य पदाधिकारियों की तस्वीरों पर जूते-चप्पल बरसाए गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हाथों से पोस्टर भी छीन लिए। भाजपा नेता शैलेश पांडे ने भी मंत्री प्रताप सरनाईक पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाए।

मीरा रोड में पुलिस छावनी में तब्दील हुआ सभा स्थल

भाजपा ने भायंदर और मीरा रोड दोनों जगह सभाओं का आयोजन किया था। शाम को भायंदर में भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने-सामने आने के बाद रात में मीरा रोड की सभा को लेकर पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती। नया नगर पुलिस ने पूरे स्टेशन परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सभा स्थल की ओर आने वाले रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, पुलिस बल और वैन तैनात की गईं, ताकि दोबारा दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा न हो।



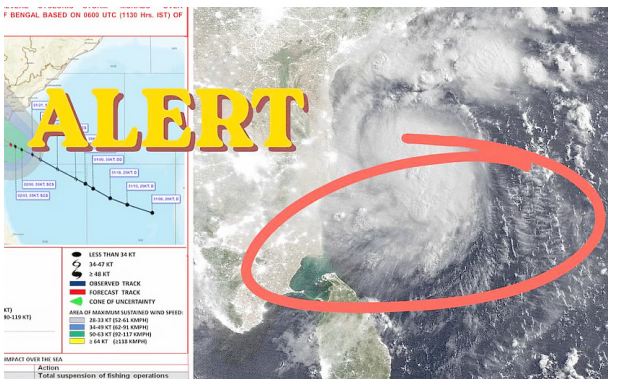
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मंत्री के इस्तीफे की मांग

भाजपा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मंत्री प्रताप सरनाईक का इस्तीफा लेने की मांग की। भाजपा का आरोप है कि मंत्री के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए और जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। नवघर में विधायक नरेंद्र मेहता मीडिया को बयान देने आने वाले थे, लेकिन वे मौके पर नहीं पहुंच सके। इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी वानखेड़े से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें जितना कहा गया था, उसी हिसाब से ग्रुप में संदेश भेजा गया था। कुल मिलाकर मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भाजपा का आंदोलन अब भाजपा और शिवसेना के बीच सीधे राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई दिया। आईना लेकर पहुंचीं शिवसेना की महिला पदाधिकारी, भाजपा की जवाबी कार्रवाई और पुलिस की गिरफ्तारी ने भायंदर से मीरा रोड तक राजनीतिक माहौल गरमा दिया।



Cyclone का नाम कैसे पड़ता है, जानें मुरासु का नाम किस देश ने रखा और क्यों ?

अर्नब के बाद नया चक्रवाती तूफान 'मुरासु' आने वाला है जो आज देर रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से एंट्री करेगा। इसे लेकर कई राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने मुरासु का दिया है नाम। ये एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है- ढोल' या 'युद्ध का नगाड़ा'। WMO और ESCAP समिति चक्रवात के नामों की सूची रखती है। भारत में मुरासु नामक साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवाती तूफान को लेकर हर कोई डरा हुआ है। उधर, IMD ने भी इसे लेकर कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, 2 नवंबर की आधी रात को मुरासु आंध्र प्रदेश के नेल्लोर-नरसापुर तट से टकराएगा। ऐसे में जानते हैं कि आने वाले इस चक्रवाती तूफान का नाम कैसे पड़ा और इसे ये नाम किस देश ने दिया है। मुरासु का असर भारत के कई जिलों में पड़ने वाला है। आज और कल आंध्र प्रदेश के 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान से न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश की प्रबल संभावना है। भारत ने नाम रखा 'मुरासु' चक्रवात इस बार 'मुरासु' चक्रवात तूफान का नामकरण भारत द्वारा किया गया है। ये एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है- ढोल' या 'युद्ध का नगाड़ा'। प्राचीन समय में इस ताल वाद्य यंत्र का उपयोग मुनादी करने या प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लोगों को सतर्क करने के लिए किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में बना ये चक्रवाती तूफान (Cyclone Murasu) आंध्र प्रदेश के तट की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके लैंडफॉल के दौरान 100 से 120 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका



है। आखिर चक्रवात का नाम 'मुरासु' ही क्यों रखा ? भारतीय मौसम विभाग ने इस चक्रवात का नाम मुरासु इसलिए रखा ताकि लोग इसे आसानी से याद रख सकें और सतर्क रहें। आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले इस चक्रवात को तमिल नाम मिलना इस बात का संदेश देता है कि ऐसा नाम रखकर वे उस इलाके के लोगों को उनकी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पड़ता है आने वाले Cyclone का नाम दरअसल, अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक, चक्रवात के नाम रखने की एक खास प्रक्रिया होती है। सबसे आसान नाम को ही चुना जाता है जो वहां के क्षेत्रीय लोगों से जुड़ा हो लेकिन व्यक्ति विशेष न हो। उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले साइक्लोन के नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की समिति द्वारा तैयार सूची के आधार पर रखे जाते हैं। इस सूची में 13 देशों द्वारा सुझाए गए नाम शामिल हैं, हर देश बारी-बारी से एक-एक चक्रवात के नाम सुझाकर रख देते हैं। ऐसे में जब-जब कोई नया चक्रवाती तूफान आता है तो उसे उस सूची में से एक नया नाम दे दिया जा है।

700% किराया बढ़ने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- मत करिए हवाई यात्रा

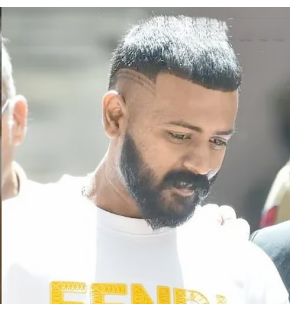
हवाई किराये में 700% तक बढ़ोतरी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि हवाई यात्रा मत कीजिए। दिवाली-छठ से पहले कई रूट पर टिकट के दाम बढ़े हैं। हवाई किराये में 700% तक बढ़ोतरी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस जे. विक्रम नाथ ने टिप्पणी की, 'मत करिए हवाई यात्रा, अगला केस।' दिवाली-छठ से पहले कई रूट पर हवाई टिकट के दाम दो से तीन गुना तक बढ़ने का दावा। हवाई किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो टूक जवाब दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि विमान का किराया 700 फीसदी तक बढ़ गया है। यह एक जरूरी सेवा है



और इस तरह किराये में बढ़ोतरी करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जे. विक्रम नाथ ने कहा, "मत करिए हवाई यात्रा। चलिए आगे बढ़िए, अगला केस।" सरकार ने एयरलाइंस को दी किराया तय करने की छूट केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसके तहत एयरलाइंस को हवाई टिकट का किराया तय करने की छूट दी गई है। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनके मुताबिक, किराया बढ़ाने के लिए एयरलाइंस को सरकार से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, किसी अपरिहार्य स्थिति में सरकार विमानन कंपनियों को निर्देश जारी कर सकती है। फिर महंगा हो सकता है सफर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में तेजी के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने विमान ईंधन (ATF) और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के मुताबिक, दिल्ली में ATF की कीमत 137.12 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 138.50 रुपये प्रति लीटर हो गई है। विमान ईंधन की कीमतों में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को ATF के दाम में 16 रुपये प्रति लीटर की बड़ी वृद्धि हुई थी। वहीं, सितंबर में 6.28 रुपये और अगस्त में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे से एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ सकती है। ऐसे में हवाई किराये पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है।

सुकेश चंद्रशेखर केस में सुनवाई टली, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही नहीं पहुंची कोर्ट; अदालत ने लगाई फटकार





सुकेश चंद्रशेखर केस में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही कोर्ट में नहीं पहुंची। 200 करोड़ रुपये के ठगी, जबरन वसूली मामले में अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। सुकेश चंद्रशेखर केस में सुनवाई टली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नोरा फतेही को भेजा समन अब 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के ठगी और जबरन वसूली मामले में नोरा फतेही आरोपी नहीं, बल्कि सरकारी गवाह हैं। लेकिन आज सुनवाई के दौरान वे कोर्ट नहीं पहुंची जिसे लेकर अदालत ने उन्हें समन भेजा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में 2 नवंबर को मामले की सुनवाई थी लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। जिसके बाद अदालत ने उन्हें फटकार सुनाते हुए कहा कि सुनवाई को हल्के में नहीं ले सकते। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी करते हुए नोरा को 6 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। ऐसे में मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

झुंझुनूं में 11 हजार वोल्ट की लाइन से टकराई मशीन, करंट लगने से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत



राजस्थान के झुंझुनूं के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान मशीन 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। हादसे में आठ मजदूरों की मौत और तीन घायल हुए। झुंझुनूं के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आई। करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही रोड़ी मिलाने वाली मशीन ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। मशीन में करंट फैलते ही वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाए, बिहार में नितिन नबीन का कांग्रेस पर निशाना, बोले- दर्ज क्यों नहीं कराईं आपत्तियां

बिहार के भागलपुर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर भी सवाल उठाए। बिहार के भागलपुर में सोमवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। नितिन नबीन ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि विपक्ष की कुर्सी खतरे में है। विपक्षी दल अपनी राजनीतिक नाकामियों से सीखने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नितिन नबीन ने विपक्ष पर साधा निशाना भागलपुर के लाजपत पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता को भ्रमित करने



का प्रयास कर रहे हैं। रा SIR के लिए एक तय प्रक्रिया क्या है? नितिन नबीन ने प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि SIR के लिए एक तय प्रक्रिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पूरे 60 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस और RJD के पास इतने कम कार्यकर्ता थे कि कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। मगरमच्छ के आंसू बहा रहा विपक्ष कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि अपनी चिंताओं को उठाने के लिए हर स्तर पर मिले मौकों का इस्तेमाल करने के बजाय, कांग्रेस ने केवल मगरमच्छ के आंसू बहाए। और जब पूरी SIR प्रक्रिया पूरी हो गई, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वे न तो विधानसभा में और न ही जनता के बीच कोई मुद्दा उठा पाए, और 2025 के चुनावों में जनता ने उन्हें इसके लिए सबक सिखाया। मलीला मैदान में कांग्रेस ने झूठ का बीज बोया आज, जब भाजपा और NDA गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे देश में पदयात्रा निकाल रहे हैं, वहीं विपक्ष कल दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखा था और झूठ के बीज बोने में व्यस्त था। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च का नेतृत्व करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, बिहार में ही SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) प्रक्रिया शुरू हुई थी, और कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसे ही कई झूठ फैलाने में लगे हुए थे। इंडुडिया गठबंधन की पार्टियों को जमकर लताड़ा इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए नितिन नबीन ने कहा, "यह विपक्षी गुट चाहे वह बिहार में तेजस्वी यादव हों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, या दिल्ली में AAP जिसे भाजपा और दिल्ली की जनता दोनों ने पूरी तरह से नकार दिया था।

ना सुप्रिया सुले बोलीं, ना ही संजय राउत... राहुल गांधी हमेशा करते हैं महाराष्ट्र की उपेक्षा, नवनाथ बन का हमला

नवनाथ बन ने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रैली में सुप्रिया सुले और संजय राउत को बोलने का मौका नहीं दिया गया। भाजपा नेता नवनाथ बन ने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। दिल्ली में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली में नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला। सुप्रिया सुले और संजय राउत जैसे प्रमुख नेताओं को मंच पर नजरअंदाज किया गया। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में INDI Alliance को लेकर तीखा हमला शुरू हो गया है। भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने अपनी पत्रकार परिषद में विरोधी गठबंधन पर महाराष्ट्र के प्रति द्वेष व पूर्वाग्रह रखने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा नेता नवनाथ बन ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में महाराष्ट्र के किसी भी नेता को मंच से संबोधन का मौका नहीं दिया गया। सुप्रिया सुले और संजय राउत को नहीं मिला मौका नवनाथ बन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और शरद पवार गुट के नेता दिल्ली में आयोजित इस रैली में भाग लेने गए थे, लेकिन राहुल गांधी और INDI गठबंधन ने उन्हें भाषण देने का अवसर तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम सुप्रिया



सुले को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, संजय राउत जो रोजाना सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। बन का आरोप है कि राहुल गांधी का महाराष्ट्र के प्रति हमेशा से भेदभावपूर्ण रवैया रहा है और इस रैली से गठबंधन की यह मानसिकता साफ उजागर हो गई है। फर्जी AI तस्वीरों और खाली कुर्सियों पर घेरा भाजपा प्रवक्ता ने रैली में जुटी भीड़ पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि रामलीला मैदान की क्षमता करीब 50 हजार लोगों की है, लेकिन वहां 50 प्रतिशत कुर्सियां खाली पड़ी थीं और केवल 20 से 25 हजार लोग ही एकत्र हो सके थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कम भीड़ को छुपाने के लिए कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने AI से तैयार की गई फर्जी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया। बन ने कहा कि एआई को कमांड देते समय भी भारी चूक हुई; असल में रैली स्थल पर ऊपर छप्पर लगा हुआ था, जबकि एआई जनरेटेड फोटो में बिना छप्पर के भीड़ दिखा दी गई। दही-हंडी की तरह 10 परतें बनानी पड़तीं संजय राउत द्वारा रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने के दावे पर चुटकी लेते हुए नवनाथ बन ने कहा कि यदि रामलीला मैदान में 10 लाख लोग आते, तो लोगों को दही-हंडी उत्सव की तरह एक के ऊपर एक 10 परतें बनाकर खड़ा होना पड़ता। बन ने कहा कि आंकड़े फुलाकर बताना संजय राउत की पुरानी आदत है। इसके अलावा, इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर उन्होंने तंज कसा कि उनके पास हफ्ते के सात दिनों के लिए अलग-अलग प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं सोमवार को राहुल गांधी, मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, बुधवार को ममता बनर्जी, गुरुवार को अखिलेश यादव और शुक्रवार को उद्धव ठाकरे।

CM नंबर 1 बने योगी आदित्यनाथ, बेस्ट चीफ मिनिस्टर श्रेणी में शीर्ष पर यूपी के मुख्यमंत्री

सर्वे में शामिल कुल 15 मुख्यमंत्रियों में शीर्ष दस को 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर' और 11वें से 15वें स्थान तक के मुख्यमंत्रियों को विशेष 'मुख्यमंत्री पंचरत्न' श्रेणी में स्थान दिया गया। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट सर्वे 2026 में योगी आदित्यनाथ देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री 897 अंकों के साथ नंबर वन तीन से चार महीने तक चली सर्वे प्रक्रिया 15 मुख्यमंत्रियों को किया गया शामिल फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के संयुक्त 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्वे 2026' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी को 1000 में से सर्वाधिक 897 अंक मिले हैं। सर्वे में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता, कार्यशैली, जनस्वीकार्यता और शासन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। सर्वे में कुल 15 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें शीर्ष दस को 'बेस्ट



चीफ मिनिस्टर' और 11वें से 15वें स्थान तक के मुख्यमंत्रियों को विशेष 'मुख्यमंत्री पंचरत्न' श्रेणी में स्थान दिया गया है। तीन स्तरीय प्रक्रिया से तैयार हुई अंतिम रैंकिंग फेम इंडिया मैगजीन का 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्वे 2026' एशिया पोस्ट के सहयोग से करीब तीन से चार महीने तक संचालित किया गया। इसमें मुख्यमंत्रियों के प्रति आम जनता की धारणा, प्रबुद्ध वर्ग की राय और आम नागरिकों के अनुभवों को समझने के लिए तीन स्तरीय सर्वे प्रक्रिया अपनाई गई। पहले चरण में सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया के विभिन्न मंचों पर मुख्यमंत्रियों से संबंधित प्रतिक्रियाओं, चर्चाओं, समाचारों और जनधारणाओं का अध्ययन किया गया। दूसरे चरण में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों, बुद्धिजीवियों और विशिष्ट व्यक्तियों की राय एवं आकलन को शामिल किया गया। तीसरे चरण में आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके विचार, अनुभव और दृष्टिकोण जाने गए। इन तीनों चरणों से प्राप्त सूचनाओं और प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के बाद मुख्यमंत्रियों का दस निर्धारित मानकों पर मूल्यांकन किया गया। सभी मानकों पर प्राप्त अंकों को जोड़कर 1000 अंकों के पैमाने पर अंतिम रैंकिंग तैयार की गई। दस प्रमुख मानकों पर हुआ मूल्यांकन सर्वे में मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए दस प्रमुख मानक निर्धारित किए गए थे।

इनमें सुशासन, कानून-व्यवस्था, व्यक्तित्व, छवि, कार्यक्षमता, प्रभाव, विभागों की समझ, लोकप्रियता, दूरदर्शिता तथा कार्यशैली और परिणाम शामिल हैं। सुशासन के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा की गुणवत्ता को परखा गया। कानून-व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और कानून के शासन को महत्व दिया गया। वहीं, व्यक्तित्व एवं छवि में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और जनता के बीच विश्वसनीयता का आकलन किया गया।

समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना के लिए बनेंगे 8 आधुनिक युद्धपोत; 53,866 करोड़ को मिली मंजूरी



भारतीय नौसेना के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये में 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट बनेंगे। GRSE और गोवा शिपयार्ड को निर्माण की जिम्मेदारी मिली। जानें इनकी खासियत। समंदर में अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने 8 आधुनिक युद्धपोतों के लिए तीन कंपनियों के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 'नेक्स्ट जनरेशन कोरवेट' (NGCs) हासिल करने के वास्ते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन अनुबंधों पर 02 नवंबर को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इन अनुबंधों के तहत, GRSE पांच कोरवेट का निर्माण करेगा, जबकि GSL बाकी तीन कोरवेट बनाएगा। भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और क्षमता यह परियोजना भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

सुनेत्रा पवार के बिना NCP के 6 बड़े नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात, इधर डिप्टी सीएम ने मुंबई में बुलाई बैठक



महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय के बंटवारे की चर्चा के बीच NCP के 6 बड़े नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। NCP के 6 वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रफुल पटेल सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और छगन भुजबल शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी को वित्त विभाग वापस मिलने की अटकलों के बीच हुई है। सुनेत्रा पवार ने पार्टी में किसी भी आंतरिक मतभेद या दरार की खबरों को खारिज किया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 6 बड़े नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

दिल्ली में सोनिया गांधी ने लालू यादव से की मुलाकात, स्वास्थ्य का हालचाल लिया; याद किए यूपीए के दिन

राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी ने लालू यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लालू यादव ने यूपीए के पुराने दिन को याद किया। सोनिया गांधी ने दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की सांसद मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य का हालचाल जाना स्थास्थ्य संबंधित जांच के लिए दिल्ली में लालू प्रसाद यादव हैं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार, 2 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचीं। यह मुलाकात लालू यादव की बेटी और लोकसभा सांसद मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। सोनिया गांधी ने लालू यादव के स्वास्थ्य का हालचाल लिया और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं। स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए दिल्ली में



लालू लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वे नियमित चिकित्सा जांच के लिए दिल्ली आए हुए हैं और उनका इलाज एम्स में चल रहा है। परिवार के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू यादव रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली आए थे। उन्होंने रविवार को खुद सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें इस बारे में बताया था। सोनिया गांधी ने खुद लालू यादव से मिलने की इच्छा जताई थी। एक्स पर शेयर की गई तस्वीरें तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी और सोनिया जी का पुराना और अच्छा रिश्ता रहा है। दोनों ने कठिन परिस्थितियों में एक-दूसरे का साथ दिया है। आज की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य लालू जी के स्वास्थ्य का हालचाल जानना था। दोनों काफी समय से नहीं मिले थे। लालू यादव ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर साझा कीं। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी उनके आवास पर पहुंचीं और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुईं। लालू यादव ने याद किए यूपीए के दिन उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान युवाओं, किसानों, जवानों और आम लोगों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार कानूनों का जिक्र किया। लालू यादव ने यह भी याद दिलाया कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बिहार के विकास के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई थी। इस मुलाकात को इंडिया गठबंधन के संदर्भ में भी देखी जा रही है।

सम्पादकीय

पानी खत्म हो जाने पर विकास भवनों का क्या उपयोग है?

प्रकृति की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजना बनाना विकास का विरोध करना नहीं है। बल्कि, इसका अर्थ है विकास को टिकाऊ बनाना। सरकार को समय रहते यह बात समझ लेनी चाहिए: जब पानी खत्म हो जाएगा, तो न तो विकास का प्रचार, न उद्योगपतियों का मुनाफा, और न ही धार्मिक समारोहों की भव्यता प्यास बुझा पाएगी! अब समय आ गया है कि सरकार के विकास मॉडल को सूखे के आईने में परखा जाए! एक ऐसी सरकार जो निर्माण कार्य को गति दे रही है, उद्योगों को पानी मुहैया करा रही है और प्रकृति का विनाश कर रही है, जबकि पानी की कमी का खतरा मंडरा रहा है, वह विकास नहीं कर रही है; बल्कि भविष्य के संकटों की नींव रख रही है। यदि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में नदियों, नालों और खाइयों का जलस्तर फरवरी-मार्च में हमेशा इतना कम हो जाता है, तो इस वर्ष यह केवल चिंता का विषय नहीं है; यह एक गंभीर चेतावनी है। क्या सरकार इस संकट से अवगत है? या क्या संकट के वास्तव में दरवाजे पर दस्तक देने तक इस पर ध्यान न देना सरकार की नीति है? मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में निर्माण कार्य में तेज़ी आई है। नई इमारतों, व्यावसायिक परिसरों, बुनियादी ढांचे और बढ़ते शहरीकरण के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या इस बढ़ती मांग को उपलब्ध जल संसाधनों से पूरा किया जा रहा है? क्या नए निर्माणों के लिए परमिट देते समय भविष्य में पानी की आपूर्ति का ठोस आकलन किया जाता है? या फिर इमारतें बनाने की होड़ लगी है, लेकिन इस बात का कोई समाधान नहीं है कि उनमें रहने वाले लोगों को पानी कहां से मिलेगा? विकास के नाम पर जनसंख्या और पानी की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी प्रकृति पर छोड़ दी गई है, यह किस तरह का विकास है? क्या उद्योगों का मुनाफा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या लोगों की प्यास? डेटा सेंटर, इथेनॉल उत्पादन, शीतल पेय उद्योग, शराब उत्पादन, कपड़ा उद्योग आदि जैसे कई क्षेत्रों को पानी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उद्योग की पानी की आवश्यकताएँ, रोजगार सृजन और आर्थिक योगदान अलग-अलग होते हैं। इसलिए, सभी उद्योगों को पूरी तरह बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल पानी के उपयोग को प्राथमिकता देने का है। जब पीने के पानी की कमी की संभावना हो, तो क्या सरकार को इस बारे में नीति नहीं बनानी चाहिए कि किस उद्योग को कितना पानी दिया जाए, कौन सा उद्योग अपने संसाधित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करे और किन उत्पादों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जाए? शीतल पेय, शराब, कपड़ा उद्योग और अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए आम आदमी से पानी का कम से कम उपयोग करने की अपील की जाती है। डेटा सेंटर जैसी डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित सुविधाओं की योजना बनाते समय, उनकी वास्तविक जल खपत, शीतलन तकनीक और स्थानीय जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों को साफ करने और फिर बारिश न होने पर सूखे का रोना रोने की इस विडंबना को हम कब तक सहन करते रहेंगे? जंगलों को नष्ट करके हम बारिश की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? स्थानीय जल चक्र, मिट्टी की नमी, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल महत्वपूर्ण हैं। वर्षा कई कारकों से प्रभावित होती है। फिर भी, जंगलों को नष्ट करना और पारिस्थितिक स्थिरता को खतरे में डालना हमारी जल सुरक्षा की नींव को ही कमजोर कर रहा है। कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन के लिए, जहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, पेयजल, स्वच्छता, स्नान घाट और अन्य सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या इतने बड़े आयोजन की योजना बनाते समय स्थानीय नागरिकों की जल आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का पारदर्शी आकलन करना आवश्यक नहीं है? धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए भी, जल प्रतिबंधों की अनदेखी करने का किसी को अधिकार नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बड़ी परियोजनाओं के लिए पानी उपलब्ध कराते समय स्थानीय निवासियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। जनता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि कितना पानी उपलब्ध है, इसकी लागत कितनी होगी और इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। जब जल संकट गंभीर हो जाता है, तो खारे पानी को मीठा बनाकर उपयोग करने का विकल्प सामने रखा जाता है। खारे पानी को मीठा बनाने की परियोजनाएं निश्चित रूप से उपयोगी हो सकती हैं। हालांकि, इन्हें पूरा करना आसान नहीं है और न ही ये सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान हैं। खारे पानी को मीठा बनाने के बाद भी, कृषि के लिए इसका उपयोग करना स्वतः ही लागत प्रभावी नहीं हो जाता। फसलों के प्रकार, पानी की गुणवत्ता, ऊर्जा लागत और परिवहन लागत पर विचार करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, यह मान लेना मूर्खता होगी कि खारे पानी को मीठा बनाने का विकल्प उपलब्ध होने मात्र से जल संकट का समाधान हो गया है। इसके बजाय, वर्षा जल का भंडारण, बांधों में रिसाव को कम करना, अपशिष्ट जल का उपचार और औद्योगिक उपयोग बढ़ाना, भूजल पुनर्भरण और कृषि में जल-बचत प्रथाओं का विस्तार जैसे उपायों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले, मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों में मौजूदा जल भंडार, आने वाले महीनों में अपेक्षित मांग और संभावित कमी का पारदर्शी लेखा-जोखा जनता के सामने रखा जाए।

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

संविधान निर्माताओं ने विधान परिषदों में शिक्षकों और स्नातकों को प्रतिनिधित्व देकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग की आवाज सदन तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समस्याओं को समझने वाले अनुभवी और जानकार लोगों को विधायी प्रक्रिया से जोड़ना था। लेकिन बदलते सामाजिक हालात, चुनावों के बढ़ते राजनीतिकरण, धनबल और कम मतदान ने इस व्यवस्था की मूल भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर विभिन्न क्षेत्रों के योग्य विशेषज्ञों को राज्यसभा की तर्ज पर मनोनीत करने का सुझाव सामने आ रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल सामान्य निर्वाचन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सदन तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि विधायी संस्थाओं में समाज के अलग-अलग वर्गों, विषयों के जानकारों और अनुभवी व्यक्तियों को उचित स्थान मिले। इसी सोच के तहत संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। इन सदस्यों का चयन साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से किया जाता है। इसी तरह राज्यों में विधान परिषदों के गठन के पीछे भी एक व्यापक उद्देश्य था। विधान परिषद को राज्य की विधायी व्यवस्था का ऐसा सदन माना गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से आने वाले अनुभवी लोग अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर कानून निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकें। इसी उद्देश्य से विधान परिषदों में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन में इन वर्गों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के पीछे क्या थी सोच? शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के पीछे संविधान निर्माताओं की सोच यह थी कि समाज के ऐसे लोगों को भी विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले, जो शिक्षा, ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को समझते हैं। सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और व्यापक जनमत का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से उन लोगों को सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को गहराई से समझते हों। शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों की समस्याओं, विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, सुविधाओं और शैक्षणिक नीतियों से सीधे जुड़े रहते हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा की गई कि वे शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को सदन में उठाएंगे और उनके समाधान के लिए ठोस सुझाव देंगे। इसी तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के माध्यम से ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने की परिकल्पना की गई, जो उच्च शिक्षा प्राप्त होने के साथ-साथ अपने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को समझते हों। उनसे यह अपेक्षा थी कि वे केवल अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि क्षेत्र विशेष की जरूरतों और आम लोगों की समस्याओं को भी सदन में प्रभावी ढंग से रखेंगे। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही था कि विधान परिषद में ऐसे प्रतिनिधि पहुंचें, जिनके पास अनुभव, विषय की समझ और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो। वे विधेयकों पर विचार करते समय केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यावहारिक और विशेषज्ञता के आधार पर भी अपनी राय रख सकें। समय के साथ बदल गई चुनावों की तस्वीर हालांकि, मौजूदा समय में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। जिस उद्देश्य से इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया था, वह उद्देश्य कई जगह कमजोर पड़ता दिखाई देता है। इन चुनावों में भी अब राजनीतिक दलों का प्रभाव लगातार बढ़ा है।

उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने तक राजनीतिक हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। कई बार चुनाव का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षकों की समस्याएं, युवाओं के रोजगार, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता या क्षेत्रीय विकास नहीं रह जाता। इसके बजाय उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में जुट जाते हैं। चुनाव जीतने की रणनीति, संगठनात्मक ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे माहौल में उन लोगों के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, जिनके पास विषय का गहरा ज्ञान तो है, लेकिन बड़े स्तर पर चुनाव प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक समर्थन नहीं है। नतीजतन, कई बार योग्य और अनुभवी लोगों के बजाय वे उम्मीदवार आगे निकल जाते हैं, जो चुनावी रणनीति और प्रबंधन में अधिक सक्षम होते हैं।

चुनाव प्रबंधन और धनबल बन रहे हैं निर्णायक कारक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव भी अब चुनावी प्रबंधन से अछूते नहीं रह गए हैं। मतदाताओं तक पहुंच बनाना, चुनावी संगठन तैयार करना, प्रचार करना और मतदान के दिन अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना उम्मीदवारों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस उम्मीदवार का संगठन मजबूत होता है और जिसके पास चुनाव प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, उसे कई बार दूसरों के मुकाबले बढ़त मिल जाती है। इसके विपरीत, किसी क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाला, शिक्षा या सामाजिक समस्याओं की अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति केवल इसलिए पीछे रह सकता है, क्योंकि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी से कमजोर हो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था

संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले प्रतिनिधियों का चयन यदि कुछ नेताओं के फैसले पर निर्भर रहेगा, तो राजनीति में योग्य, अनुभवी और साफ-सुथरी छवि वाले लोगों के लिए अवसर सीमित होते रहेंगे। राजनीतिक दलों की टिकट वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका की प्राथमिक चुनाव प्रणाली तथा यूरोपीय देशों में प्रचलित पार्टी-आधारित चयन प्रक्रियाओं से सीख लेने की जरूरत है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहां नियमित रूप से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। करोड़ों मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कमजोरी ऐसी भी है, जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है। यह कमजोरी राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया से जुड़ी है। देश में चुनाव तो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का अवसर किसे मिलेगा, इसका फैसला अक्सर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व या कुछ प्रभावशाली नेताओं के हाथों में रहता है। किसी क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, यह तय करने में वहां के आम कार्यकर्ताओं, पार्टी सदस्यों और स्थानीय मतदाताओं की भूमिका कई बार सीमित रह जाती है। परिणामस्वरूप, जनता को चुनाव के समय उन्हीं उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जिन्हें राजनीतिक दलों ने पहले से मैदान में उतार दिया है। इस स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब लोकतंत्र में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया में भी उसकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? उच्च सदनों की मूल भावना और मौजूदा राजनीतिक वास्तविकता देश का उच्च सदन राज्यसभा हो या राज्यों का उच्च सदन विधान परिषद, इनके गठन के पीछे एक महत्वपूर्ण विचार यह था कि विधायी संस्थाओं में ऐसे अनुभवी और विषयों के जानकार लोग भी पहुंचें, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में अपना विशेष योगदान दे सकें। उच्च सदनों को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दूसरा मंच बनाने के बजाय विचार-विमर्श, अनुभव और विशेषज्ञता का केंद्र बनाने की कल्पना की गई थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था इसी सोच का उदाहरण है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों को संसद में स्थान देने का उद्देश्य यह था कि देश की नीतियों और कानूनों पर चर्चा करते समय विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। लेकिन व्यवहार में उच्च सदनों में भी राजनीतिक समीकरणों का प्रभाव दिखाई देता है। राज्यसभा और विधान परिषदों में पहुंचने वाले कई प्रतिनिधियों का चयन राजनीतिक दलों की रणनीति, चुनावी गणित और संगठनात्मक समीकरणों के आधार पर होता है। ऐसे में यह आशंका बनी रहती है कि जिन सदनों में विशेषज्ञता और अनुभव को विशेष महत्व मिलना चाहिए, वहां भी राजनीतिक निष्ठा और दलगत हित अधिक प्रभावी हो रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अयोग्य होता है या विशेषज्ञता रखने वाला हर व्यक्ति अच्छा जनप्रतिनिधि साबित होगा। लेकिन यह जरूर विचारणीय है कि उच्च सदनों में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा चयन प्रक्रिया में क्या सुधार किए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र केवल चुनाव कराने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों के भीतर भी पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक लोकतंत्र होना आवश्यक है। राजनीतिक दल ही जनता और शासन व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे उम्मीदवारों का चयन करते हैं, चुनावी मुद्दे तय करते हैं और सरकार बनाने के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं। ऐसे में यदि राजनीतिक दलों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित रहेगी, तो उसका असर पूरी चुनावी व्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है। टिकट वितरण में स्थानीय कार्यकर्ताओं, पार्टी के सक्रिय सदस्यों और क्षेत्र के लोगों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता, तो योग्य उम्मीदवारों के सामने भी चुनाव लड़ने का अवसर सीमित हो सकता है। कई बार किसी क्षेत्र में लंबे समय से सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति, स्थानीय समस्याओं की अच्छी समझ रखने वाला कार्यकर्ता या अपने पेशे में उल्लेखनीय योगदान देने वाला नागरिक भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बन पाता। इसके बजाय राजनीतिक समीकरणों, चुनाव जीतने की संभावित रणनीति और शीर्ष नेतृत्व के आकलन को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रक्रिया में यह भी जरूरी नहीं कि उम्मीदवार की सामाजिक स्वीकार्यता, सार्वजनिक जीवन में योगदान और क्षेत्र की समस्याओं के प्रति उसकी समझ को पर्याप्त प्राथमिकता मिले। नतीजतन, उम्मीदवार चयन का निर्णय स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय संगठन के भीतर सीमित हो सकता है। टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं होने से जनता के विकल्प सीमित किसी भी चुनाव में मतदाता के सामने उम्मीदवारों के विकल्प राजनीतिक दलों द्वारा तय किए जाते हैं। मतदाता मतदान के दिन अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकता है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका सामान्यतः नहीं होती। यही भारतीय चुनाव व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है। किसी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले नागरिक यह चाह सकते हैं कि उनके क्षेत्र से कोई शिक्षित, अनुभवी, ईमानदार और स्थानीय समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति चुनाव लड़े। लेकिन यदि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देते, तो मतदाता के पास उपलब्ध विकल्प सीमित हो जाते हैं। यहां सवाल केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है।

अलग-अलग दलों में टिकट वितरण की प्रक्रिया और उसके नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार चयन में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका व्यापक रूप से महत्वपूर्ण रहती है।

टीवीएफ के संघर्ष से लेकर 100 करोड़ की कामयाबी तक, अरुणाभ कुमार की जिंदगी में एकता कपूर बनीं बड़ा सहारा



टीवीएफ के फाउंडर अरुणाभ कुमार के 20 साल के कड़े संघर्ष के बाद बनी पहली फिल्म 'द वन'बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अरुणाभ कुमार ने 2006 में फिल्ममेकर बनने का सपना लेकर मुंबई का रुख किया था। असफलताओं के बाद अरुणाभ कुमार ने 2012 में TVF की शुरुआत की। एकता कपूर के भरोसे से फिल्म 'द-वन' बनाने का सपना पूरा हुआ। अरुणाभ कुमार की पहली थिएट्रिकल फिल्म 'द-वन' का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के करीब पहुंचा। सपनों के शहर मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाने का सफर किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। इस बात की मिसाल पेश करते हुए द वायरल फीवर यानी टीवाएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार ने अपने संघर्ष के उन पन्नों को पलटा है, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2006 में जब उन्होंने मुंबई में कदम रखा था, तो उनका एकमात्र सपना एक बड़ा फिल्ममेकर बनने का था। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं थी और लगातार मिलने वाली असफलताओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ एड्स और टेलीविजन की दुनिया में भी उन्हें केवल मायूसी ही हाथ लगी थी। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि साल 2012 तक स्थिति यह आ गई थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे थे। उम्मीदें टूटने पर जब बदलना पड़ा रास्ता अरुणाभ कुमार ने फिल्म डायरेक्शन के अपने शुरुआती सपने को कुछ समय के लिए विराम दे दिया। अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2012 में टीवीएफ की नींव रखी। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि डिजिटल कंटेंट की दुनिया में क्रांति लाने वाला यह मंच आगे चलकर इतिहास रचेगा। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक से बढ़कर एक बेहतरीन और दिल को छू लेने वाले शोज दिए, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हालांकि, पर्दे के पीछे सिनेमा बनाने की वह कसक उनके दिल में आज भी जिंदा थी। एकता कपूर के एक भरोसे ने बदल दी किस्मत अरुणाभ कुमार के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जब उन्होंने पूरी तरह से फीचर फिल्म बनाने का विचार अपने दिल से निकाल दिया था। ऐसे मुश्किल वक्त में जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आईं। एकता कपूर के अटूट भरोसे, सही मार्गदर्शन ने ही उन्हें अपनी फिल्म 'द-वन' को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, उन्होंने अपने लंबे समय के साथी और डायरेक्टर दीपक मिश्रा की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने उनकी सालों पुरानी कल्पना को अपनी बेहतरीन समझ के साथ पर्दे पर जीवंत कर दिया। मास बेल्ट में धूम मचा रही है फिल्म 'द वन' 20 साल का लंबा इंतजार, अनगिनत संघर्ष और एक अधूरा सा लगने वाला सपना आखिरकार अब हकीकत में बदल चुका है। टीवीएफ के बैनर तले बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की थिएट्रिकल फिल्म 'द-वन' को दर्शकों का अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है।

एक्टर अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन, टीवी इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर



अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके दोस्त रूपेश सोनार के मुताबिक, सोते समय सीजर अटैक आने से उनकी मौत हुई। अभिनेता जल्द टीवी पर वापसी की तैयारी कर रहे थे। फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन के बाद एक बार फिर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी है। छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाने वाले एक्टर अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अनुज ठाकुर ने 27 अक्टूबर 2026 को दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि ये खबर अब जाकर सामने आयी है। अनुज ने अपने एक्टिंग करियर में कई फेमस टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका में नजर आ चुके हैं। उनके अचानक दुनिया से चले जाने के कारण उनके परिवार, दोस्तों के अलावा टीवी इंडस्ट्री भी गमजदा है। उनके करीबी दोस्त रूपेश सोनार ने उनके निधन के खबर की पुष्टि की है।

पहले बनवाया वीडियो, विरोध हुआ तो दीया मिर्जा को बताने लगी हिंदू विरोधी, BMC मेयर रितु तावडे का बयान वायरल



अभिनेत्री दीया मिर्जा के प्रदूषण-मुक्त दिवाली अभियान पर विवाद गहरा गया है। मुंबई की मेयर रितु तावडे ने अब दीया मिर्जा को हिंदू विरोधी बताया है। मुंबई की मेयर रितु तावडे ने अभिनेत्री दीया मिर्जा को बयान दिया। दिया मिर्जा को बीएमसी कार्यक्रम या आधिकारिक पोर्टल में शामिल नहीं किया जाएगा। मेयर रितु तावडे का आरोप- दीया मिर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करती हैं। हिंदुत्व का विरोध करने वालों को बीएमसी प्रशासन में कोई जगह नहीं मिलेगी। अभिनेत्री दीया मिर्जा के प्रदूषण-मुक्त दिवाली अभियान को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मुंबई की मेयर रितु तावडे ने दीया मिर्जा के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्हें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम और पोर्टल से पूरी तरह से बाहर रखने का ऐलान किया है। BMC के कार्यक्रमों में दीया मिर्जा की एंट्री बैन मेयर रितु तावडे ने मीडिया से बात करते हुए दीया मिर्जा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने और हिंदुत्व विरोधी बयानबाजी करने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि हम दीया मिर्जा को बीएमसी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, खासकर आधिकारिक BMC डिजिटल पोर्टल पर तो उन्हें बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। वह भविष्य में हमारे द्वारा आयोजित किसी भी अन्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, क्योंकि वह लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करती आई हैं। रितु तावडे ने पार्टी और नगर निगम के रुख को साफ किया। उन्होंने कहा कि एक मेयर के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा और हमारी पार्टी का रुख बेहद स्पष्ट है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने आधिकारिक पोर्टल या मंच पर जगह नहीं देंगे जो हिंदुत्व का विरोध करता हो या देश के नेतृत्व का अपमान करता हो। मुंबई सभी धर्मों के लोगों को गले लगाता है मुंबई शहर की विविधता और सांस्कृतिक ताने-बाने का जिक्र करते हुए मेयर रितु तावडे ने कहा कि यह शहर हमेशा से हर वर्ग और धर्म के लोगों को गले लगाता रहा है, लेकिन किसी को भी धार्मिक आस्थाओं या राजनीतिक नेतृत्व पर तंज कसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों को जवाब दिया जाएगा मेयर रितु तावडे ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व या हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ बोलता है चाहे उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय या पहचान कुछ भी हो उसे उसी भाषा में कड़ा जवाब दिया जाएगा।

बीएमसी प्रशासन ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बर्दाश्त करेगा। दीया मिर्जा ने पीएम मोदी के बयानों का विरोध किया अभिनेत्री दीया मिर्जा के अभियान पर बीएमसी मेयर रितु तावडे ने कहा कि अगर हम दीया मिर्जा की पूरी प्रोफाइल देखें, तो पता चलता है कि उन्होंने नर्मदा परियोजना और समान नागरिक संहिता (UCC) का विरोध किया है।

इन 5 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है यह कीवी बैटर



भारत-न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू हो रही 5 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और डेरिल मिचेल सहित इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में पांच ऐसे खिलाड़ी है जिनपर सभी की नजरें रहेगी विराट कोहली का यह न्यूजीलैंड का आखिरी दौरा माना जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज बुधवार, 4 नवंबर से होने जा रहा है।

'हां, मैं थका हुआ हूं', न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान



मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज जीतने के बाद कोचिंग के भारी दबाव और मानसिक थकान पर खुलकर बात की है। जानें गंभीर ने टीम सिलेक्शन और आलोचनाओं पर क्या कहा। न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान गंभीर ने एक इंटरव्यू में अपनी मानसिक स्थिति और कोचिंग के अनुभवों को साझा किया गंभीर ने कहा कि, ईमानदारी से कहूं तो, हां, मैं थका हूं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि टीम इंडिया का कोच होने के भारी दबाव और बड़ी जिम्मेदारियों ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत की 3-2 से रोमांचक जीत के बाद गंभीर ने एक इंटरव्यू में अपनी मानसिक स्थिति और कोचिंग के अनुभवों को साझा किया। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे इस दबाव को झेलने और परिस्थितियों को संभालने के लिए पूरी तरह से मजबूत हैं। 'हाँ, मैं थका हुआ हूँ'- गौतम गंभीर दरअसल, एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए गौतम गंभीर ने अपनी मानसिक स्थिति और भारतीय टीम के कोच पद के साथ आने वाले दबाव पर खुलकर बात की। गंभीर ने कहा कि, ईमानदारी से कहूं तो, हां, मैं थका हूं, लेकिन मैं इसे संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। मैं जब तक संभव हो, इसे झेलने की ताकत रखता हूं। मैं दबाव झेल सकता हूं, मैं आलोचनाओं की गोली खा सकता हूं। गंभीर ने आगे कहा कि आखिरकार वे भी एक इंसान हैं, इसलिए कभी-कभी थका हुआ महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन वे इसे अच्छे से संभालने में सफल रहे हैं। लोकप्रिय नहीं, सही फैसले लेना मेरा काम टीम चयन और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के मुश्किल फैसलों पर गंभीर ने अपना कड़ा रुख साफ किया।

बांग्लादेश में भड़का कपड़ा मजदूरों का गुस्सा, सैलरी की मांग पर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, ढाका में तनाव

बांग्लादेश में कम मजदूरी के विरोध में हजारों कपड़ा मजदूर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने 30,000 टका मासिक वेतन की मांग की, जबकि पुलिस के साथ हिंसक झड़पें भी हुईं। बांग्लादेश में हजारों कपड़ा मजदूर कम मजदूरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी मौजूदा वेतन करीब 13,000 टका से बढ़ाकर 30,000 टका चाहते हैं ढाका और गाजीपुर में पुलिस के साथ झड़पें हुईं, आंसू गैस छोड़ी गई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार प्रदर्शनकारियों का मकसद सरकार के किसी कानून में बदलाव या सत्ता परिवर्तन नहीं है। इस बार मुद्दा कम मजदूरी से जुड़ा हुआ है। इसके विरोध में हजारों कपड़ा मजदूर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है। सोमवार को हजारों कपड़ा मजदूरों ने एक मेन हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर दोगुने से भी अधिक करने की मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन ढाका के साथ-साथ देश के कई अन्य इलाकों में भी हो रहे हैं। कितना बड़ा है बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग? बांग्लादेश का



नाम दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग से जुड़े देश के तौर पर लिया जाता है। चीन के बाद बांग्लादेश ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात करने वाला देश है। कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांडों के कपड़े बांग्लादेश में ही तैयार किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सस्ते मजदूर हैं। हालांकि, बांग्लादेश के कई औद्योगिक केंद्रों पर मजदूरों के शोषण के आरोप भी लगते रहे हैं। सोमवार को ढाका के उत्तर में स्थित गाजीपुर में सैकड़ों मजदूरों ने ढाका-तंगेल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। इसके बाद जब पुलिस भीड़ को हटाने गई तो प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। गाजीपुर के अलावा मीरपुर इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया। सरकार बना रही है मजदूरी बोर्ड मजदूरों का यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब सरकार ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि वह गारमेंट उद्योग में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा के लिए एक 'मजदूरी बोर्ड' बनाने जा रही है। बांग्लादेश के लिए कपड़ा उद्योग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में इसका अहम योगदान है। हालांकि मजदूर नेताओं का आरोप है कि उद्योग से मिलने वाले लाभ का नाममात्र का मजदूरों को मिलता है। उनका कहना है कि मजदूरों की समस्याएं सिर्फ इस बोर्ड के गठन से हल नहीं होंगी। क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी मजदूर 30,000 टका मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं, जो उनके वर्तमान वेतन से दोगुना से भी अधिक है। वर्तमान में बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग से जुड़े मजदूर प्रतिमाह औसतन करीब 13,000 टका कमाते हैं।

वियतनाम दौरे पर NSA अजीत डोभाल, रक्षा सहयोग की समीक्षा कर और मजबूत करने पर बातचीत की



राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा सहयोग की समीक्षा की। हनोई की यात्रा पर देश के एनएसए अजीत डोभाल वियतनाम के डिप्टी पीएम के साथ मुलाकात की दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग की समीक्षा की है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को हनोई में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, जनरल फान वान गियांग के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इस क्षेत्र में आपसी जुड़ाव को और गहरा करने पर सहमति जताई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग में हुई प्रगति पर चर्चा की और अपने संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया। रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई दूतावास ने पोस्ट में लिखा कि NSA अजीत डोभाल ने आज वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की। जनरल गियांग वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इस क्षेत्र में अपने जुड़ाव को और गहरा करने पर सहमति जताई। हनोई की यात्रा पर अजीत डोभाल डोभाल रविवार को वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर हनोई पहुंचे। इस यात्रा के दौरान, वे दोनों देशों के बीच 'एनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' की समीक्षा करने के लिए वियतनामी नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने NSA का स्वागत करते हुए 'X' पर पोस्ट किया, "वियतनाम में आपका स्वागत है! बता दें कि यह यात्रा मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति 'तो लाम' की भारत यात्रा के बाद हो रही है, जब भारत-वियतनाम संबंधों को 'एनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' के स्तर तक बढ़ाया गया था।

भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में FTA लागू करने पर चर्चा की, सीमा शुल्क सहयोग और बाजार तक पहुंच पर मंथन

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 30 अक्टूबर 2026 को ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास और 'बिजनेसयूरोप' द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बिजनेस राउंडटेबल को संबोधित किया। ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के बीच मीटिंग हाई लेवल मीटिंग में मुफ्त व्यापार समझौता लागू करने पर चर्चा वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की ईयू के अधिकारी के साथ चर्चा भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों के दौरान अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा की। इसके साथ ही, उन्होंने बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी बातचीत की। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी थे मौजूद



मीटिंग में व्यापार और आर्थिक सुरक्षा महानिदेशालय की महानिदेशक डिट्टे जूल जोर्गेनसेन; अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी महानिदेशालय के महानिदेशक कोएन डोएन्स; और कराधान एवं सीमा शुल्क संघ महानिदेशालय के महानिदेशक गेरासिमोस थॉमस शामिल थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जोर्गेनसेन के साथ हुई बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी व्यापार को आसान बनाने, बाजार तक पहुंच सुधारने, आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और मजबूत बनाने, तथा भारत और EU की कंपनियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने के तरीकों पर चर्चा की। एफटीए लागू करने पर चर्चा हुई उन्होंने एक निष्पक्ष, संतुलित और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, वे प्रक्रियात्मक और कार्यान्वयन से जुड़े बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।

फेस्टिवल के बीच हवाई किराए को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, विशेष परिस्थिति में दखल देने की अनुमति



सरकार ने त्योहार के बीच हवाई किराए को लेकर नया नियम जारी किया है। इसके अनुसार विशेष परिस्थिति में दखल की अनुमति होगी। फेस्टिवल के बीच सरकार ने हवाई किराए को लेकर नए नियम जारी किए हैं एयरलाइन टिकट की कीमतों में दखल देने की अनुमति होगी विशेष परिस्थिति में दखल देने की बात कही गई है त्योहार के बीच सरकार ने हवाई किराए को लेकर नए नियम जारी की है। मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हवाई किराए काफी ऊंचे हो गए हैं। इसे लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। अब सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत, सरकार को विशेष परिस्थितियों में और जनहित को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन टिकट की कीमतों में दखल देने की अनुमति होगी।

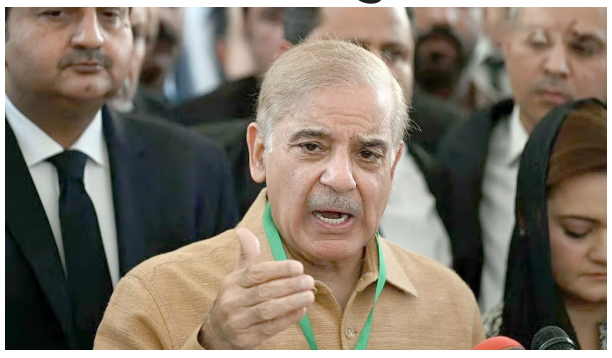
हेब्रोन शहर से हट गई इजरायल की सेना, 10 दिनों के अभियान के बाद फैसला; घेराबंदी के कारण काफी नुकसान

इजरायल की सेना 10 दिनों से ज्यादा दिनों तक सैन्य अभियान चलाने के बाद हेब्रोन शहर से हट गई है। अब इस इलाके पर फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों का पूरा नियंत्रण है। हेब्रोन शहर से हट गई इजरायल की सेना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई 10 दिनों से ज्यादा सैन्य अभियान चलाए गए हैं इजरायली सेना वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर से हट गई है। अल जजीरा की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के गवर्नर के हवाले से बताया गया है कि 10 दिनों से ज्यादा समय तक घेराबंदी करने के बाद, इजरायली सेना हेब्रोन शहर से वापस चली गई है। न्यूज नेटवर्क ने बताया कि हेब्रोन के गवर्नर खालिद दुदीन के अनुसार, 10 दिनों से ज्यादा चले सैन्य अभियान के बाद इजरायली सेना पूरे हेब्रोन शहर से हट गई है। दुदीन ने चैनल को बताया



कि अब इस इलाके पर फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों का पूरा नियंत्रण है, और जो परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, वे अब वापस लौट सकते हैं। आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा रिपोर्ट के मुताबिक, 23 अक्टूबर को शहर के पास हुए एक हमले के बाद इजरायली सेना ने हेब्रोन की घेराबंदी कर दी थी। इस हमले में इजरायली रक्षा बलों (IDF) के दो सैनिक मारे गए थे। स्थानीय नगर पालिका के अनुसार, इस हमले के बाद 3,300 से ज्यादा फिलिस्तीनी प्रभावित हुए या उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। कई घर नष्ट हो गए और कारोबार बंद हो गए। शहर के मेयर, यूसुफ अल-जबारी ने 31 अक्टूबर को अल जजीरा को बताया था कि घेराबंदी के कारण हर दिन 12 मिलियन शेकेल (3.8 मिलियन डॉलर) से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है। बुनियादी ढांचे को 1.9 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, जबकि स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में लगभग 160,000 डॉलर का नुकसान हुआ है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित अल-जबारी ने आगे बताया कि IDF ने 15 घरों और अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया है और 327 व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर किया है। मेयर ने यह भी बताया कि लगभग 80,000 छात्र 10 दिनों तक स्कूल नहीं जा पाए। अल-जबारी के अनुसार, फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था में हेब्रोन की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है और यह घेराबंदी एक तरह की सामूहिक सजा है।

घुटनों पर आया पाक! भारत से दुश्मनी में गंवाए 40 बिलियन डॉलर, अब रिश्ते सुधारने की गिड़गिड़ाहट



भारत-पाक व्यापार पर रोक से पाकिस्तान को 40 बिलियन डॉलर का नुकसान, कपड़ा और दवा उद्योग पर पड़ा गहरा असर। अब रिश्ते सुधारने की अपील कर रहा है पाकिस्तान।भारत के साथ ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। देशों के बीच ट्रेड रुकने से पाक को लगभग 4,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। भारत के साथ व्यापार रुकने से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार बंद होने के कारण गंभीर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान-इंडिया बिजनेस काउंसिल (पीआईबीसी) के अध्यक्ष नूर मोहम्मद कसूरी ने कहा है कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार रुकने से पाकिस्तान को लगभग 4,000 करोड़ डॉलर यानी 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से व्यापारिक संबंधों को फिर से शुरू करने की अपील की है। उनका मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू होता है, तो इससे न केवल व्यापारियों बल्कि आम जनता को भी लाभ हो सकता है। भारत से व्यापार बंद कैसे पड़ रहा भारी? नूर मोहम्मद कसूरी के अनुसार, भारत से व्यापार बंद होने के बाद पाकिस्तान की कंपनियों को आवश्यक सामान और कच्चा माल अन्य देशों से खरीदना पड़ रहा है। इससे सामान लाने का खर्च बढ़ गया है और डिलीवरी में अधिक समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दवा उद्योग पहले भारत से कई महत्वपूर्ण कच्चे माल खरीदता था। अब अन्य देशों से आयात करने के कारण लागत बढ़ गई है। कसूरी का कहना है कि यदि भारत से आयात फिर से शुरू होता है, तो पाकिस्तान हर साल 200 से 300 करोड़ डॉलर तक की बचत कर सकता है। पाक में किस-किस सेक्टर पर असर? भारत के साथ व्यापार रुकने से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान में कपास उत्पादन कम होने के कारण कपड़ा कंपनियों को ब्राजील, मिस्र, चीन और अमेरिका जैसे देशों से कपास आयात करनी पड़ रही है, जिससे लगभग 500 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त खर्च हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कई किसान अब कपास की खेती छोड़कर गन्ने की खेती करने लगे हैं, जिससे कपड़ा उद्योग को आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर कृषि नीतियां बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत से क्या खरीद सकता है पाकिस्तान? कसूरी के अनुसार, पाकिस्तान भारत से कई आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है, जैसे चीनी, खाद, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा-इस्पात, सब्जियां और भारी मशीनरी। उन्होंने बताया कि भारत की तेल रिफाइनरियां पाकिस्तान के नजदीक हैं, जिससे भारत से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर पाकिस्तान को कम खर्च करना पड़ेगा और सामान भी जल्दी पहुंच सकेगा। 'ट्रेड शुरू होने से दोनों देशों को फायदा' PIBC अध्यक्ष ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू होने पर दोनों देशों के व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। इससे निवेश, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है। उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, दोनों देशों में कई ऐसे स्थान हैं, जहां लोग अपने पूर्वजों के गांव और पुराने धार्मिक स्थलों को देखने की इच्छा रखते हैं। कसूरी ने कहा कि आर्थिक सहयोग में राजनीतिक मतभेद बाधा नहीं बनने चाहिए। दोनों देशों के पुराने विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्यापारिक संबंधों की बहाली से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सकता है।

कैपिटल गेन टैक्स पर राहत के संकेत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेशकों की चिंताओं पर कही बड़ी बात



वित्त मंत्री ने विदेशी निवेशकों की कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी चिंताओं पर विचार करने का संकेत दिया। उन्होंने मौजूदा टैक्स ढांचे में बदलाव पर कई पहलुओं पर विचार करने की बात कही। FPI की कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी चिंताओं पर सरकार विचार करेगी। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने इसका संकेत दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि FII की निकासी से चिंताएं और बढ़ गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की कैपिटल गेन टैक्स लेकर चिंताओं को सुनेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फाइनेंशियल एक्सप्रेस लीडरशिप अवाड्र्स में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि बाजार में बदले माहौल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने कर ढांचे में बदलाव को मांगों को तेज कर दिया है। हालांकि, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि मौजूदा कर ढांचा 2023 में भी वही था, जब भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया था। उन्होंने कहा कि 2023 में भी जब निवेश का फ्लो रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी टैक्स का ढांचा वैसा ही था जैसा आज है। FII की निकासी से बढ़ी चिंताएं- वित्त मंत्री कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज हालात बदल गए हैं। एफआईआई की निकासी हुई है और चिंताएं भी बढ़ गई हैं। मैं इन सब बातों पर विचार करूंगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार मौजूदा टैक्स व्यवस्था में कोई भी बदलाव करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करेगी और साथ ही वैश्विक निवेशकों द्वारा जताई गई चिंताओं को भी ध्यान में रखेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि टाटा समूह के भीतर चल रहे मुद्दे- जिनमें चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति को लेकर मतभेद और टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग शामिल हैं, आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिए जाएंगे। टाटा ग्रुप विवाद पर वित्त मंत्री ने क्या कहा? वित्त मंत्री सीतारमण ने इस मामले को एक संवेदनशील मुद्दा बताया, जिसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक और कारोबारी पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसे सार्वजनिक रूप से विवाद करने के बजाय संबंधित पक्षों को आपस में सुलझा लेना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में टाटा समूह के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू, इसे खड़ा करने में पारसी समुदाय के योगदान और उन विभिन्न क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें टाटा की कंपनियां काम करती हैं। 'टाटा भारतीय इकोनॉमी का अहम हिस्सा' वित्त मंत्री ने कहा कि मैं टाटा की ब्रांड वैल्यू और इसे एक बड़ा वैश्विक ब्रांड बनाने में पारसी समुदाय के योगदान को जानती हूं। मुझे यह भी पता है कि टाटा ग्रुप किन-किन क्षेत्रों में सक्रिय है। इसलिए, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे दोनों पक्षों को आपसी सहमति से सुलझा लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संस्थान के लिए लंबे समय तक सार्वजनिक विवाद चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

हफ्ते के पहले दिन बाजार में हरियाली, 1,233 अंक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी में 387 अंकों की उछाल



भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। जहां सेंसेक्स 1,233 अंक और निफ्टी 387 अंक चढ़कर बंद हुआ कमोडिटीज और एनर्जी स्टॉक्स ने बाजार को सहारा दिया। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,233.25 अंक बढ़कर 75,692.78 पर क्लोज हुआ। शेयर बाजार की तेजी को कमोडिटीज और एनर्जी स्टॉक्स से सहारा मिला। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,233.25 अंक या 1.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,692.78 और निफ्टी 387.70 अंक या 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,440.80 पर बंद हुआ। बाजार की तेजी को सहारा कमोडिटीज और एनर्जी स्टॉक्स से मिला। सूचकांकों में निफ्टी ऑयल एंड गैस 5.95 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटीज 4.01 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर्स थे। मिडकैप और स्मॉलकैप में उछाल इसके अलावा, निफ्टी एनर्जी 3.92 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 3.70 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 3.21 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.70 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 2.34 प्रतिशत, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 2.23 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे अधिक तेजी दिखाने वाले सूचकांक थे। दूसरी तरफ, निफ्टी मीडिया -0.76 प्रतिशत, निफ्टी आईटी -0.50 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक -0.14 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा -0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 682.15 अंक या 1.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,983.40 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 131.70 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

पृष्ठ 1/8 का शेष

मुंबई के सरकारी अस्पतालों में

सर्जरी से पहले दो योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जांच कराना अनिवार्य है। साथ ही, मरीजों को काउंसलिंग और मेडिकल प्रमाणपत्र लेना भी जरूरी होता है। सायन और नायर अस्पतालों में इस सर्जरी की फीस 5,000 रुपए है, जबकि केईएम में बड़ी सर्जरी के लिए 2,000 रुपए लिए जाते हैं। हालांकि, इलाज के दौरान दवाओं और अन्य मेडिकल सामग्री का खर्च पूरी तरह अलग होता है। निजी अस्पतालों में 3 लाख से 5 लाख रुपए में यही सर्जरी की जाती है। प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पलातों का खर्च बेहद कम है। इंटरसेक्स मरीजों के इलाज के हाल लिंग परिवर्तन से जुड़े मामलों में भी विभिन्न अस्पतालों के आंकड़े काफी अलग हैं। नायर अस्पताल में हर साल लगभग 8 से 9 इंटरसेक्स मरीज इलाज के लिए दर्ज किए जाते हैं। इसके विपरीत, सायन अस्पताल में ऐसे किसी भी मरीज के इलाज का आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वहीं, जेजे अस्पताल में भी पिछले तीन साल के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

विलेज रोड में 5 मिनट में 14

लोगों के अनुसार, खुले में चलने वाले फूड स्टाल्स के आसपास बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते मंडराते रहते हैं। इसके चलते अब तक राहगीरों को कुत्तों के काटने की दो से तीन घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे पैदल चलने वालों विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों में भारी डर का माहौल है। सड़क पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का डर, अनियंत्रित अवैध पार्किंग, देर रात तक होने वाला शोरगुल और आवारा कुत्तों का आतंक अब स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई इसके अलावा, रात के दो बजे तक खाने-पीने के अवैध स्टॉल और दुकानें खुली रहती हैं, जिसके कारण सड़क पर भारी भीड़भाड़ और यातायात जाम हमेशा बनी रहती है। नागरिकों का यह भी कहना है कि देर रात तक चलने वाली इन गतिविधियों की वजह से इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी काफी बढ़ गया है। इससे आसपास की सोसाइटियों और इमारतों में रहने वाले रहिवासियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। प्रशासनिक लापरवाही बन रही बड़ी मुसीबत नागरिकों का कहना है कि जिस सड़क से क्षेत्र के लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की उम्मीद थी, वही मार्ग अब उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका और स्थानीय प्रशासन से तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। लोगों की मांग है कि डीपी रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, देर रात तक गैरकानूनी तरीके से संचालित होने वाले स्टॉल और दुकानों पर लगाम लगाई जाए तथा आवारा कुत्तों की समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाए।

सोने-चांदी में भयंकर मंदी के हालात, तेजी के बड़े लक्ष्य देने वाले फंड हाउस अब खामोश!



जनवरी 2026 में सोना वैश्विक बाजार में 5625 डॉलर प्रति औंस और मुंबई में 1.82 लाख रुपये प्रति दस ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था। लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 30 से 57 प्रतिशत तक टूटे दाम सोना 42 हजार रुपये सस्ता हुआ चांदी 2.46 लाख रुपये हुई सस्ती सुरक्षित निवेश माने जाने वाली दोनों कीमती धातुओं में पिछले 4 वर्षों में जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थीं और तेजी के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे, अब उससे दोगुनी रफ्तार से कीमतें गिर रहीं हैं। सोना-चांदी में जैसे अप्रत्याशित जबरदस्त तेजी आई थी, वैसे ही अप्रत्याशित भारी मंदी आने लगी है। यह देखकर हर कोई हैरान है। इस साल जनवरी में सोना वैश्विक बाजार में 5625 डॉलर प्रति औंस और मुंबई में 1.82 लाख रुपये प्रति दस ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था, लेकिन अब गिरते हुए 3884 डॉलर प्रति औंस यानी 1.40 लाख रुपये प्रति दस ग्राम पर ही आ गया है। अर्थात पीली कीमती धातु में 30 प्रतिशत यानी 42 हजार रुपये प्रति दस ग्राम की भारी गिरावट आ चुकी है और निवेशकों का इस साल का पूरा फायदा लगभग साफ हो गया है। चांदी में तो और बुरा हाल, आधे हुए दाम चांदी में तो और बुरा हाल है। इस साल जनवरी में चांदी की कीमत वैश्विक बाजार में 122 डॉलर प्रति औंस और मुंबई में 4.27 लाख रुपये प्रति दस ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंची थी, लेकिन अब गिरते हुए 49 डॉलर प्रति औंस यानी 1.81 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ही आ गयी है। अर्थात सफेद कीमती धातु में 57 प्रतिशत यानी 2.46 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की भंयकर गिरावट आ चुकी है और चांदी इस साल फायदे की बजाय नुकसान में आ गयी है। मुंबई में चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2026 को 2.35 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, लेकिन अब 1.81 लाख रुपये ही रह गयी है। अर्थात निवेशक 54 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के घाटे में आ गए हैं।

देशी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 1.02 करोड़ की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

भिवंडी क्राइम ब्रांच-2 की कार्रवाई; आरोपी के पास से 5 लाख रुपये नकद बरामद

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी:देशी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 2 लाख 17 हजार रुपये की ठगी करने के आरोप में ठाणे क्राइम ब्रांच की भिवंडी यूनिट-2 ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्पेश वसंत तारमाळे (पाटील) (32) निवासी पडलेगांव, शील डायघर, ठाणे के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शिकायतकर्ता को देशी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने का भरोसा दिलाकर अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अलग-अलग समय पर नकद और आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1 करोड़ 2 लाख 17 हजार रुपये वसूल किए। आरोप है कि मोटी रकम लेने के बावजूद आरोपी ने न तो लाइसेंस दिलाया और न ही शिकायतकर्ता की रकम वापस की।इस मामले में उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक



737/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(7), 318(4), 371(2) और 3(7) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच के आधार पर गिरफ्तारी मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट-2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राऊत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट-2 कर रही है। अन्य पीड़ितों से भी संपर्क की अपील ठाणे पुलिस ने अपील की है कि यदि आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति को भी देशी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर ठगी की है, तो वह भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट-2 से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराए। पुलिस ने नागरिकों को सरकारी लाइसेंस और अन्य सुविधाएं दिलाने के नाम पर मिलने वाले प्रलोभनों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

भिवंडी में मोबाइल टावरों से 1.44 लाख की बैटरी और केबल चोरी

दापोडे, गुंदवली, सुरई और वळपाडा के टावरों को बनाया निशाना; नारपोली पुलिस में मामला दर्ज

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी तालुका में मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर बैटरी और केबल चोरी करने की घटनाएं सामने आई हैं। अज्ञात चोरों ने दापोडे, गुंदवली, सुरई गांव और वळपाडा स्थित मोबाइल टावरों से करीब 1 लाख 44 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया। इस मामले में नारपोली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता विकांत विजय महाकाळे (38) इंडस रेडियंट मोबाइल टावर कंपनी, पुणे में कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि भिवंडी तालुका के विभिन्न इलाकों में कंपनी के मोबाइल टावरों पर लगी बैटरियां और केबल चोरी हो गई हैं। चोरी की घटनाएं 6 मई 2025 से 18 सितंबर 2026 के बीच होने की आशंका है।चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 1 लाख 44 हजार रुपये बताई गई है। कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर नारपोली पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 1308/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस हवलदार जाधव कर रहे हैं। पुलिस टावरों से बैटरी और केबल चोरी करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है।

मुंबई के सरकारी अस्पतालों में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के आंकड़े चौंकाने वाले, सायन में 35 ऑपरेशन

मुंबई के सरकारी अस्पतालों में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा और मरीजों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। आरटीआई से मुंबई के सरकारी अस्पतालों में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया। पिछले तीन वर्षों में सायन अस्पताल में 35 जेंडर सर्जरी दर्ज की गईं। जेजे और नायर अस्पताल में केवल एक-एक सर्जरी हुई, जबकि केईएम में एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। सरकारी अस्पतालों में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा और मरीजों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई के सायन अस्पताल यानी लोकमान्य टिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में



पिछले तीन साल में 35 सर्जरी हुईं। वहीं, जेजे और नायर अस्पताल में सिर्फ एक-एक सर्जरी हुई है। इसके अलावा, केईएम अस्पताल में एक भी सर्जरी का खाता नहीं खुला है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता चेतन कोठारी द्वारा मांगी गई थी। सायन अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी २ विभाग ने बताया कि पिछले तीन साल में 535 टॉप और बॉटम सर्जरी की गई। इसके अलावा, जनरल सर्जरी विभाग ने मार्च 2023 से अब तक 14 सर्जरी की जानकारी दी है। इन मरीजों की आगे की न देखभाल प्लास्टिक सर्जरी विभाग संभालता है। अस्पताल का कहना है कि ई सर्जरी की सफलता या असफलता तय करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित पैमाना तय नहीं किया गया है। जेजे और नायर अस्पताल में केवल 1 सर्जरी, बेहद कम आंकड़े जेजे अस्पताल में वर्ष 2023-24 के दौरान केवल एक जेंडर सर्जरी हुई, जिसकी सफलता दर 100 प्रतिशत दर्ज की गई, हालांकि, इसके बाद के दो वित्तीय वर्षों में एक भी सर्जरी नहीं की गई। इसी तरह, नायर अस्पताल में भी केवल एक सर्जरी दर्ज की गई और उसकी सफलता दर भी 100 प्रतिशत बताई गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि इन बड़े अस्पतालों में यह सुविधा अभी शुरुआती चरण में है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मरीजों को जांच कराना अनिवार्य सायन अस्पताल में ...शेष 7 पर

विलेज रोड में 5 मिनट में 14 हादसे !अवैध पार्किंग और स्टॉल से बढ़ा खतरा, आवारा कुत्तों से सहमी कांदिवली

मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित सिंह एस्टेट और ठाकुर विलेज को जोड़ने वाले डीपी रोड पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से स्थानीय नागरिक परेशान हैं। कांदिवली पूर्व के सिंह एस्टेट-ठाकुर विलेज डीपी रोड पर लगातार सड़क हादसों से नागरिकों में चिंता। वायरल वीडियो में पांच मिनट के भीतर 14 हादसों का दावा, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, हाल के दिनों में सड़क हादसों में दो लोगों की मौत और चार गंभीर रूप से घायल। कांदिवली पूर्व स्थित सिंह एस्टेट को ठाकुर विलेज से जोड़ने वाले डीपी रोड पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले



रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी रोष और चिंता का माहौल है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें महज पांच मिनट के भीतर इस मार्ग पर 14 एक्सीडेंट होने का सनसनीखेज दावा किया गया है। हालांकि, इस वायरल दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब से इस सड़क का निर्माण हुआ है, तब से यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान यहां हुई विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत होने और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी सामने आई है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़क के दोनों तरफ अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पहले से ही व्यस्त रहने वाला मार्ग और अधिक संकरा हो जाता है। कुत्तों के काटने की कई घटनाएं, स्थानीय लोगों में फैला डर इन तमाम समस्याओं के बीच आवारा कुत्तों का आतंक भी स्थानीय लोगों के लिए एक गंभीर मुसीबत बन चुका है। ...शेष 7 पर

कशेली में फ्लैट का दरवाजा तोड़कर 3.47 लाख के जेवर और नकदी चोरी

बेडरूम की अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने के आभूषण ले उड़े चोर; नारपोली पुलिस में मामला दर्ज

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी के कशेली स्थित स्वराज नगर में चोरों ने एक फ्लैट का दरवाजा तोड़कर करीब 3 लाख 47 हजार रुपये के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर बेडरूम की अलमारी का लॉकर तोड़ा और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस मामले में नारपोली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, उर्मिला अपार्टमेंट, स्वराज नगर, कशेली निवासी अमन संतोष सिंह (28) के फ्लैट में 1 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 3:30 से 4:30 बजे के बीच चोरी हुई। अज्ञात चोर ने किसी औजार की मदद से घर के दरवाजे का कुंडा काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद बेडरूम में रखी लकड़ी की अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे करीब 3 लाख 40 हजार रुपये के सोने के आभूषण और 7 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गया।चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 3 लाख 47 हजार रुपये बताई गई है। पीड़ित की शिकायत पर नारपोली पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 1310/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(अ) और 331(3) के अनुसार मामला दर्ज किया गया है।मामले की जांच पुलिस हवलदार हरेश म्हात्रे कर रहे हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्र में जांच कर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है।

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486